

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3148
11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

अनुसंधान एवं विकास पर सरकारी और निजी व्यय

†3148. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर सरकारी व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार, सरकारी संस्थानों को अपने संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी इसी तरह की पहल की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)**

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान 6 प्रमुख वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किया गया सरकारी व्यय निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

विभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	4893.56	5140.26	4436.26	4002.67	5661.45
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डीएसआईआर/सीएसआईआर)	4198.82	5122.99	5852.14	6088.57	6350.54
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)	2259.10	2850.73	2044.74	1467.34	2460.13
अंतरिक्ष विभाग (डीओएस)	9474.41	12473.84	10139.43	10704.07	11725.75
परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एंड डी क्षेत्र)	5913.91	6111.46	7006.76	7337.42	9226.66

(करोड़ रुपये में)

विभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस)	1274.54	2184.43	1568.86	2394.56	3632.78
कुल	28014.34	33883.71	31048.19	31994.63	39057.31

स्रोत: केंद्र सरकार के अनुदान मांगें, व्यय बजट, भारत सरकार (विभिन्न वर्ष)

*संशोधित अनुमान

(ख) से (ग): सरकार देश भर में सार्वजनिक और निजी संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) व्यय को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें बढ़ी हुई निधि, संस्थागत सुधार और लक्षित मिशन-मोड पहले शामिल हैं। प्रमुख कदमों में शामिल हैं: वैज्ञानिक विभागों के लिए आबंटन में क्रमिक वृद्धि; विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभरते क्षेत्रों में मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए आर एंड डी संस्थानों को वित्तीय सहायता; सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अन्य नवाचारी हाईब्रिड वित्तपोषण तंत्र जैसे पोर्टफोलियो-आधारित वित्तपोषण तंत्रों के माध्यम से सहयोगात्मक अनुसंधान वित्तपोषण के लिए नए अवसरों का सृजन; कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों के अंतर्गत कॉर्पोरेट क्षेत्र को आर एंड डी निवेश करने की अनुमति देना, जिसमें इनक्यूबेटर्स, संस्थागत अनुसंधान और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए सहायता शामिल है; आदि। इसके अलावा, कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं: राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार हेतु निजी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष का शुभारंभ; केंद्र सरकार द्वारा 14,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान और गैर-सरकारी स्रोतों से अतिरिक्त निधि जुटाकर अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की स्थापना; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (बजट परिव्यय: 6,003.65 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय अंतरविषयक साइबर-भौतिकी प्रणाली मिशन (बजट परिव्यय: 3,660 करोड़ रुपये), भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (बजट परिव्यय: 76,000 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन आदि जैसे राष्ट्रीय मिशनों का शुभारंभ। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आर एंड डी में व्यय बढ़ाने और अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भू-स्थानिक नीति 2022, अंतरिक्ष नीति 2023 और बायोई3 नीति 2024 जैसे सहायक नीतिगत रूपरेखाएं लागू की गई हैं।
